NEWSLETTER
CSC Creating Rural Entrepreneurship, Redefining e-Governance

Weekly Newsletter of CSC e-GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED March 31, 2020

हाईलाइट

सीएससी केंद्रों में जागरुकता के लिए क्रिएटिव डिस्प्ले

प्रिय वीएलई,

सरकार द्वारा देश भर में कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए 21 दिनों के तालाबंदी की घोषणा के साथ, हमारा यह कर्तव्य है कि हम टेलीमेडिसिन, बैंकिंग आदि की डिजिटल सेवाओं तक पहुँच के साथ नागरिकों की सहायता करें।

हम आपके साथ इस मेल में कुछ क्रिएटिव शेयर कर रहे हैं जिन्हें आप अपने सीएससी पर प्रिंट-आउट ले कर डिस्प्ले लगा सकते हैं। ये क्रिएटिव ऑनलाइन जी 2 सी सेवाओं और कुछ सरकारी ऐप तक पहुंच के संबंध में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए हैं।

दिए गए लिंक से क्रिएटिव डाउनलोड करें:
https://drive.google.com/open?id=1p7OHjyIDA2D_QHFV1r09WB92H9dGOc_P

सभी वीएलई को इन क्रिएटिव का प्रिंट आउट लेना होगा और अपने सीएससी में प्रदर्शित करना होगा।

क्रिएटिव प्रदर्शित करने के लिए वीएलई को 1000 रु दिए जाएगें। एक बार वीएलई सीएससी में क्रिएटिव डालता है, तो उसे उसी की 1 से 3 अच्छी तस्वीरें क्लिक करनी होंगी और दिए गए लिंक पर अपलोड करनी होंगी: http://pmevent.csc-services.in/?r=sessionimage/event&date=2020-03-29

इसके बाद, वीएलई को क्रिएटिव के फोटो को हर 10 दिनों में तीन बार क्लिक करना होगा। वीएलई द्वारा प्रदान की गई लिंक पर फ़ोटो अपलोड करने के बाद ही राशि जारी की जाएगी।

आइए हम इस अवसर पर आगे बढें और इन कोशिशों के जरिए ज़रूरी सेवाओं वाले ज़रूरतमंद नागरिकों की मदद करें!

NEWSLETTER
CSC Creating Rural Entrepreneurship, Redefining e-Governance

Weekly Newsletter of CSC e-GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED March 31, 2020

हाईलाइट

हरियाणा में ई-पशु चिकत्सा सेवा आरंभ

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2020 यानि आज माननीय श्री ओ पी यादव, राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार) ने हरियाणा में पशु टेलीमेडिसिन सुविधा (ई-पशु चिकित्सा) का शुभारंभ किया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि 3 लाख से अधिक सीएससी ने सरकार की डिजिटल इंडिया पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स (वीएलई) ने महिलाओं, हाशिए पर रहने वाले समुदायों और ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाकर और उन्हें विभिन्न सरकारी और अन्य सेवाओं तक पहुंच के अवसर प्रदान करके भारत में क्रांति ला दी है। अब, ई-पशु चिकत्सा सेवा के शुभारंभ के साथ, वीएलई सरकार के एजेंडा को आगे ले जा रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले अयोग्य समुदाय के किसानों और पशु रखने वालों की सेवा की जा रही है।

हरियाणा सरकार के पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव श्री राजा शेखर वुंदरू ने सीएससी वीएलई के प्रयासों की सराहना की और हरियाणा में इस सेवा को शुरू करने के लिए सीएससी टीम और हरियाणा पशुपालन विभाग को बधाई दी।

हरियाणा पशुपालन विभाग के महानिदेशक डॉ ओ पी चिककारा ने कहा, "राज्य में, हम 7 पॉलीक्लिनिक्स और 22 नैदानिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से सेवा प्रदान कर रहे हैं। यह पहल हरियाणा में पशुओं के ऑनलाइन उपचार में अत्यधिक मूल्यवान साबित होगी।

लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल हसबैंड्री (LUVAS) - हिसार के कुलपति डॉ गुरदयाल सिंह ने कहा, "मैं सीएससी के ग्राम स्तरीय उद्यमियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे वास्तव में ई-पशु के क्षेत्र में क्रांति के सूत्रधार होंगे। भारत में चिकत्सा और हमें सशक्त समाज बनाने में सक्षम बनाता है। मेरा विश्वविद्यालय सेवाओं के वितरण को सक्षम करने में हमेशा सीएससी का समर्थन करेगा। "

सीएससी एसपीवी के सीईओ डॉ दिनेश त्यागी ने कार्यक्रम में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा, "भारत सरकार ने हाल ही में टेलीमेडिसिन के लिए दिशा-निर्देश लॉन्च किए हैं। वर्तमान परिदृश्य में, टेलीमेडिसिन विशेष महत्व मानता है। जानवरों के लिए टेलीमेडिसिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हरियाणा सरकार का बहुत आभारी हूं, जिसने हमें महेंद्रगढ़ में ई-पशु चिकित्सा के लिए जगह आवंटित की है। इस सेवा में, वैज्ञानिक ऑनलाइन के माध्यम से परामर्श प्रदान कर सकते हैं। हम सशक्त और डिजिटल रूप से समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में ग्रामीण लोगों के लिए सभी सेवाओं पर काम कर रहे हैं। "
सेवा के ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान राज्य और केंद्रीय टीम के सीएससी अधिकारी भी मौजूद थे।

NEWSLETTER
CSC Creating Rural Entrepreneurship, Redefining e-Governance

Weekly Newsletter of CSC e-GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED March 31, 2020

लीड़

कोरोनावायरस के दौरान एसबीआई सीएसपी (वीएलई) प्राप्त करेंगे विशेष मुआवजा

मुआवजा:-

- अतिरिक्त 3000 / - रु मासिक प्रोत्साहन भुगतान किया जाएगा
- २ रुपये प्रति Txn अतिरिक्त प्रोत्साहन
- COVID-19 के कारण सीएसपी को किसी भी घातक स्थिति के लिए एसबीआई द्वारा 10 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जाएगा।
- एसबीआई द्वारा सैनिटाइज़र / डेटॉल / सर्जिकल दस्ताने / मास्क के लिए १५०० रु का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

मुआवजे से ऊपर का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें: -

- सीएसपी को 3000 रुपये अतिरिक्त राशि का भुगतान के लिए महीने में 21 दिन खुला रहना चाहिए।
- प्रति लेनदेन २ / - रु. प्राप्त करने के लिए एक दिन में न्यूनतम ४० लेनदेन करना चाहिए और एक दिन में अधिकतम क्षमता १५० / - रु प्रतिदिन है।
- 1500 / - रुपये का लाभ उठाने के लिए, शाखा में बिल जमा करें और शाखा उसकी प्रतिपूर्ति करेगी। जीएसटी चालान होने पर कर का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
- परिवार को या उप को 10 लाख कवरेज राशि का भुगतान किया जाएगा

ध्यान दें: ऊपर दिए गए सभी मुआवजे 1 मार्च 20 से लागू होते हैं।

CSC e-GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED
Electronics Niketan, 4th Floor, DIT, Program Management Unit, 6,CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
C I N : U74999DL2009PLC192275

NEWSLETTER
CSC Creating Rural Entrepreneurship, Redefining e-Governance

Weekly Newsletter of CSC e-GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED March 31, 2020

लीड़

COD हर किसी के लिए एक वरदान

- डॉ दिनेश त्यागी

सरकार कार्यक्षमता में सुधार करने में सक्षम होगी और नागरिकों को विभिन्न कार्यालयों में जाने की अनावश्यक परेशानी से बचाया जाएगा।

हाल ही में, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज के छात्रों से नरेंद्र मोदी सरकार की "डिजिटल इंडिया" पहल से परिचित होने के दौरान पूछा गया कि उनमें से कितने लोग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सरकारी कार्यालय गए थे। उनमें से लगभग ९० फीसदी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जब उनसे पूछा गया कि उनमें से कितने लोग अपनी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सरकारी कार्यालय में वापस जाना चाहते हैं, तो प्रतिक्रिया बड़ी थी, लगभग सभी ने "नहीं" का जवाब दिया । इस प्रतिक्रिया का कारण बताने के लिए, उनमें से कई ने लंबी कतार, असहयोगी कर्मचारियों का हवाला दिया, जो एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक भेजते थे। अशिष्टता और सरकारी कर्मचारियों के अभाववादी रवैये के रूप में, कुछ और भी कारण हैं जो उन्हें वापस जाने से रोकते हैं और यह केवल राज्य प्रशासन द्वारा संचालित विभागों तक ही सीमित नहीं था, इसमें केंद्र सरकार द्वारा संचालित कार्यालय भी शामिल थे।

एक विकल्प को देखते हुए, कोई भी, विशेष रूप से नई पीढ़ी, सरकारी कार्यालयों का दौरा नहीं करना चाहती है । सरकारी कार्यालय का दौरा करने का अनुभव, भले ही यह कंप्यूटर और एयर कंडीशनर और अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस हो, आम नागरिकों, खासकर युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता है। इसके अलावा, उनके निवास स्थान से यात्रा करने या सरकारी विभाग में काम करने की असुविधा, काम पाने के लिए समय बिताने के लिए आवश्यक समय, इस तरह की सेवा वितरण के लिए प्रक्रियात्मक अस्पष्टता और विकल्प की उपलब्धता, लोगों को सरकारी कार्यालयों से दूर करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं ।

आज तकनीकी प्लेटफार्मों के माध्यम से और अंतहीन ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और सेवाओं के माध्यम से विभिन्न उत्पाद खरीदे जा रहे हैं जहां नागरिकों को ईंट और मोर्टार की दुकानों / कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। इन उभरती हुई तकनीकी प्रगति के मद्देनजर, नागरिकों की अपेक्षाओं में काफी वृद्धि हुई है और वे अपने दरवाजे पर वितरित सेवाओं के लिए भुगतान करने के इच्छुक हैं और सेवाओं के वितरण के समय और भुगतान करने की सुविधा है जिसे कैश ऑन डिलीवरी यानि (सीओडी) कहा जाता है।

वास्तव में, यह फ्लिपकार्ट था, जिसने 2007 में लॉन्च होने के बाद, अपने सीओडी भुगतान मॉडल के माध्यम से ई-कॉमर्स में क्रांति ला दी। COD मॉडल की बदौलत फ्लिपकार्ट के उत्पाद देश के दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच गए। जिन लोगों के पास ऑनलाइन बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं थी, वे ऐसे लोग थे जिन्होंने सीओडी मॉडल का प्रस्ताव रखा था।

नीलसन ग्लोबल कनेक्टेड कॉमर्स सर्वे की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग ८३ प्रतिशत दुकानदार अपने सभी ऑनलाइन खरीदों के लिए नकदी का उपयोग करते हैं। अलग-अलग ऑनलाइन धोखाधड़ी और हैकिंग के कारण ग्राहक कार्ड की जानकारी देने से भी संकोच करते हैं। इसमें कहा गया है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन इत्यादि जैसे ऑनलाइन स्टोर के लिए खरीदारों द्वारा किए गए भुगतान का बड़ा हिस्सा सीओडी था, जहां ७२ प्रतिशत महत्वपूर्ण शहरी समुदायों से और ९० प्रतिशत छोटे शहरों से थे।

ऑनलाइन खुदरा क्षेत्र फलफूल रहा है और सीओडी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इस तथ्य के बावजूद कि ई-वॉलेट और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं बढ़ रही हैं, सीओडी भुगतान मॉडल अभी भी समाज के एक बड़े हिस्से द्वारा पसंद किया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड और ई-वॉलेट जैसे भुगतान विकल्प सीओडी की तुलना में ऑनलाइन खरीद का केवल 30 प्रतिशत है। एक क्षेत्र, जो सीओडी भुगतान मॉडल को और बढ़ावा दे सकता है, वह है सरकारी सेवाओं का वितरण।

NEWSLETTER
CSC Creating Rural Entrepreneurship, Redefining e-Governance

लीड़

नागरिकों को आम तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, अधिवास / निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, चुनाव कार्ड, स्कूल / कॉलेज प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड, भूमि पंजीकरण दस्तावेज, व्यवसाय करने के लिए विभिन्न अनुमति / लाइसेंस और सामाजिक कार्यों के आयोजन की आवश्यकता होती है । सरकारी चालान या करों को दाखिल करना, विभिन्न लाइसेंस प्राप्त करना कुछ अन्य सेवाएं हैं जिन्हें घर पर वितरित किया जा सकता है।

नागरिकों को ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए, जहां वे सरकार द्वारा आवश्यक विभिन्न दस्तावेजों को संलग्न कर सकते हैं और सरकार और संबंधित संस्थानों को सत्यापन और अन्य नियत प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र / लाइसेंस / दस्तावेज अपने निवास / कार्यालय को भेजना चाहिए। नागरिक सरकार द्वारा निर्धारित कूरियर शुल्क और "शुल्क" का भुगतान करने के लिए तैयार हैं।

सीओडी गवर्नमेंट-टू-सिटिजन (जी 2 सी) सेवाओं के लिए एक व्यवसाय मॉडल है जो सरकार के साथ-साथ लोगों के लिए भी चमत्कार कर सकता है। जबकि सरकार कार्यालय सेट-अप के संदर्भ में लागत में कटौती करने और दक्षता में सुधार करने में सक्षम होगी, नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक झंझटों से बचाया जाएगा।

G2C सेवाओं के वितरण से सीओडी भुगतान मॉडल में कई फायदे होंगे क्योंकि लोगों को सेवा केंद्रों पर नहीं जाना होगा। बड़े पैमाने पर समय की बचत होगी और कम दिन भी लगेंगे । यह ग्राफ्ट में कटौती करेगा और अधिकारियों / कर्मचारियों के सिस्टम को "पहले आओ, पहले पाओ" आधार पर संसाधित करेगा और अनुचित पक्षपात को कम करेगा। G2C सेवाओं के लिए सीओडी भुगतान मॉडल सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया को फिर से परिभाषित करेगा और सही अर्थों में "सेवा" भाग को बाहर लाएगा। सरकारी सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G2C सेवाओं के लिए सीओडी एक गेम-चेंजर होगा।

NEWSLETTER
CSC Creating Rural Entrepreneurship, Redefining e-Governance

Weekly Newsletter of CSC e-GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED March 31, 2020

इम्पेक्ट

ग्रामीण भारत में कोरोनावायरस संकट पर कैसे सीएससी टेलीमेडिसिन का उपयोग दिला रहा है नागरिकों को लाभ

43 साल के मनरेगा कार्यकर्ता भूरे लाल गौर को कई दिनों से सिरदर्द, गले में खराश और नाक से सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही थी। वह मूत्र संक्रमण से भी पीड़ित थे। भूरे लाल गांव सिलपुरी, पोस्ट पदवार (जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश) में रहते हैं और सबसे पास का अस्पताल भी उनके गांव से 35 किमी की दूरी पर है। यह वह समय है जब माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर अगले 21 दिनों के लिए लॉक-डाउन' की घोषणा की है। भूरेलाल परेशान थे कि डॉक्टर के क्लिनिक की तक जाने में लॉक-डाउन' का उल्लंघन होगा और साथ ही यह उन्हे और अधिक बीमार कर सकता है।

भूरे लाल ने कहा, "मुझे बैक्टीरिया और वायरस के उस चक्र में जाने की कोई इच्छा नहीं ।" उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए, वीएलई अरुण लोधी ने उन्हें अपने सीएससी में उपलब्ध टेलीमेडिसिन सेवा के बारे में जानकारी दी। वीएलई ने भूरेलाल के घर का दौरा किया और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक डॉक्टर से परामर्श करने में मदद की, उन्हें विस्तार से समस्या बताई और दवाइयां दीं। वीएलई ने पर्चे का प्रिंटआउट प्रदान किया और मरीज को नजदीकी मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने में मदद की। भूरेलाल की तबियत ठीक है और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं ले रहे हैं। अब वह खुश है कि उसे असहनीय दर्द से राहत मिली है।

इसी तरह, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड के सुसुनीगरिया पंचायत में, वीएलई डॉ रजनी सोडेरा कोरोनवायरस विषाणु के मद्देनजर ग्रामीणों को मुफ्त टेलीमेडिसिन परामर्श प्रदान करा रही हैं। वह कहती हैं, "भारत में 2019-20 कोरोनोवायरस महामारी का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को सामने आया था और तब से मैं पूर्वी सिंहभूम में नागरिकों के लिए जागरूकता पैदा कर रही हूं और मुफ्त टेलीमेडिसिन परामर्श प्रदान कर रही हूं।"

सीएससी टेलीमेडिसिन कोविद -19 महामारी के खिलाफ एक फ्रंट-लाइन हथियार के रूप में उभरा है। बड़ी संख्या में महिलाएं, दुर्बल और बूढ़ी हैं, जो अन्यथा कोविद -19 महामारी में स्वास्थ्य सेवा के लिए अस्पताल जाने में असमर्थ हैं, सीएससी टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनका सहयोग किया जा रहा है। वर्तमान में, होम्योपैथी के अलावा, सीएससी फ्रेमवर्क आयुर्वेदिक और एलोपैथिक टेली-परामर्श का भी समर्थन करता है।

NEWSLETTER
CSC Creating Rural Entrepreneurship, Redefining e-Governance

Weekly Newsletter of CSC e-GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED March 31, 2020

इनिशिएटिव

शिवपुरी वीएलई सोसाइटी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया दान

कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए सीएससी वीएलई सोसायटी शिवपुरी ने पीएम राहत कोष में 11000 रुपए दान किया ।

सोसायटी के अध्यक्ष वैभव श्रीवास्तव और सचिव केशव शर्मा ने एसडीएम श्री आशीष तिवारी को यह चैक दान किया।

कोलारस-Csc-VLE सोसाइटी शिवपुरी द्वारा आज पीएम राहत कोष में 11000 की सहयोग राशि का चेक SDM आशीष तिवारी कोलारस को सोसाइटी अध्यक्ष वैभव श्रीवास्तव एवम सचिव केशव शर्मा ने सौपा

टेली लॉ के तहत 2 लाख मामले दर्ज

सीएससी एसपीवी ने टेली-कानून के तहत 2 लाख मामले दर्ज किए हैं। इस सफलता के लिए सभी वीएलई को बधाई।

NEWSLETTER
CSC Creating Rural Entrepreneurship, Redefining e-Governance

Weekly Newsletter of CSC e-GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED March 31, 2020

स्टेट्-स्केन

कोविद -19 महामारी के दौरान डिजी-पे के माध्यम से गरीबों की मदद करते सीएससी वीएलई

38 साल के उम्मेद कंवर एक दिहाड़ी मजदूर हैं जो राजस्थान के दौसा जिले के एक छोटे से गांव अलुडा में रहते हैं। यह दौसा से 17 किमी दूर स्थित है। कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण, उसे नौकरी से निकाल दिया, गया और वह भोजन का खर्च उठाने में असमर्थ हो गई। 26 मार्च को, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोविद -19 के प्रकोप से लड़ने में मदद के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की। उम्मेद कंवर जैसे मजदूरों के लिए, पैकेज में खाद्य सुरक्षा और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण लाभ का मिश्रण शामिल है।

वीएलई महेश कुमार सैनी अपने गांव में राहत पैकेज पर सक्रियता से जागरूकता पैदा कर रहे हैं। उम्मेद कंवर अपने सीएससी में आए और डिजी-पे के माध्यम से तुरंत 1000 रुपये का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण लाभ प्राप्त किया। यह तत्काल राहत उसे और उसके बच्चों को चल रहे कोविद -19 महामारी के दौरान मद्द देगी।

एक अन्य लाभार्थी गोपाल लाल रैगर 51 साल के मनरेगा कार्यकर्ता हैं जो अलुडा गाँव के हैं। एक दुर्घटना में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। लॉकडाउन के कारण, वह नकदी निकासी के अभाव में आवश्यक खाद्य पदार्थों को खरीदने में असमर्थ था। वीएलई अपने निवास पर गए और मनरेगा के तहत भुगतान वापस लेने की सुविधा दी।

ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ 70% भारतीय रहते हैं और अक्सर पूरी तरह से नकदी पर निर्भर रहते हैं। सीएससी डिजी-पे के माध्यम से नकद निकासी का मंच बन गया है। यह प्रणाली UIDAI द्वारा समर्थित आधार और प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी केंद्र या राज्य सरकार निकायों के मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग, और वृद्धावस्था पेंशन, आदि के तहत भुगतान की तरह सरकारी अधिकारों के संवितरण की सुविधा प्रदान करती है।

यह प्रणाली किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक / आईरिस सूचना पर आधारित है, जो किसी भी धोखाधड़ी और गैर-वास्तविक गतिविधि के खतरे को खत्म करती है। आधार अपने लाभार्थी को 'कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह' प्रमाणीकरण की सुविधा देता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सीएससी में डिजी-पे प्रोजेक्ट के तहत 4,302.78 करोड़ रुपये की निकासी के लिए कुल 44.16 लाख लेनदेन किए गए हैं।

इसके बाद, अप्रैल, 2017 से दिसंबर, 2019 की अवधि के दौरान सीएससी में डिजी-पे प्रोजेक्ट के तहत, 9,250.80 करोड़ रुपये की निकासी के लिए कुल 927.66 लाख लेनदेन किए गए थे।

अप्रैल, 2018 से दिसंबर, 2019 की अवधि के दौरान सीएससी के माध्यम से कुल 505.52 लाख लेनदेन किए गए हैं।

डिजी-पे के दौरान अप्रैल, 2018 से दिसंबर, 2019 के तहत लेनदेन की मासिक प्रवृत्ति नीचे दिए गए चार्ट में दिखाई गई है –

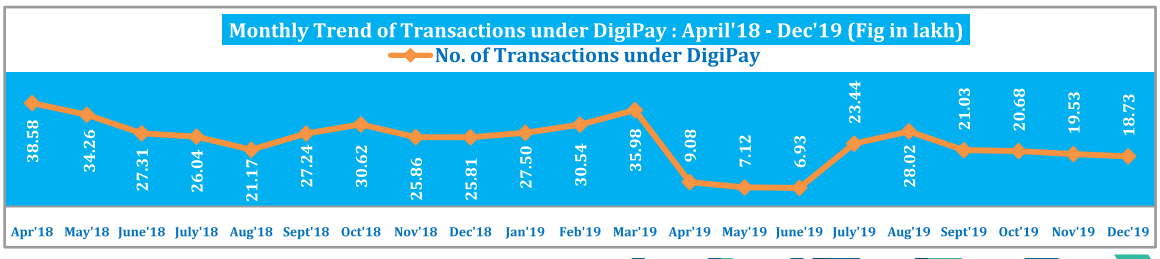

CSC e-GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED
Electronics Niketan, 4th Floor, DIT, Program Management Unit, 6,CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
C I N : U74999DL2009PLC192275

अन्य (अदर्स)

नवरात्रि स्पेशल ऑफर: वीएलई के लिए मुफ्त टीईसी कोर्स

यह सभी वीएलई के लिए टीईसी के तहत मुफ्त पंजीकरण और प्रमाणन प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है।

Toppr – अब कम कीमत पर उपलब्ध

Toppr कक्षा 5 व 12 वीं के छात्रों के लिए एक ई-लर्निंग सामग्री है। सीएससी एसपीवी वीएलई बच्चों के लिए विशेष मूल्य प्रदान करता है। यह ऑफर 30 अप्रैल, 2020 तक वैध है।

अन्य (अदर्स)

सीएससी सेवा कोविद -19 के समय में सुरक्षा और करुणा के साथ

यहां देखें वीडियो:
https://www.youtube.com/watch?v=W3dXp3XSTw4&feature=youtu.be